

(क) प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास कालोनियों में 1984-85 में दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्वास कालोनियों में इन सुविधाओं का शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में इस प्रकार की पुनर्वास कालोनियां शामिल नहीं हैं। तथापि, सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास कालोनियों में निम्नांकित अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया की जा रही है :—

1. अलग-अलग कनेक्शनों के लिए जलपूर्ति की मुख्य लाइनें;
2. मल-जल निकास;
3. बरसाती पानी की नालियों और पुलियों का सुधार करना;
4. सड़कों एवं मार्गों का सुधार करना;
5. परिधीय सेवाएं; और
6. ऊपरी टैंक और भूमिगत हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया था कि सरकार की नीति के अनुसार कार्य शीघ्र पूरा किया जा रहा है।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लेटों के लिए आवेदन-पत्र

446. श्री सज्जन कुमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लेटों

के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे गए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को 25 फरवरी, 1984 तक प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं; और

(ग) शेष लोगों को कब तक प्लॉट आबंटित कर दिए जाएंगे तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रोहिणी रिहायशी आवास योजना में विभिन्न वर्गों के प्लॉटों के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 82,384 आवेदन प्राप्त किए थे :—

वर्ग	आवेदन पत्रों की संख्या
आधिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	18,390
निम्न आय वर्ग	38,105
मध्यम आय वर्ग	25,889
	82,384

(ख) उक्त योजना में पंजीकृत 82,384 आवेदकों में से 20,389 पंजीकृतों को 25-2-84 तक प्लॉट आबंटित किए गए हैं।

(ग) शेष पंजीकृतों को प्लॉटों का आबंटन पांच वर्षों की अवधि में चरणवार किया जाएगा।

Rationalising the Law Governing the House Owner and Tenant Relationship

447. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government have had under consideration the question of rationalising the law governing the house owner and tenant relationship ; and

(b) if so, what decision has been taken in this regard and whether any legislation for the purpose is proposed to be brought before the Parliament ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :
(a) Yes, Sir.

(b) The amending bill will be brought before the Parliament after the details are finalised.

**Increase in Price of Sugar, Rice, and
Wheat Supplied Through P.D.S.**

448. SHRI MADHAVRAO SCINDIA :
SHRI SATYAGOPAL
MISRA :
SHRI RASHEED MASOOD :
SHRI RAJNATH SONKAR
SHASTRI :
SHRI B.D. SINGH :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL
SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of levy sugar, rice and wheat distributed through public distribution system have lately been increased ;

(b) if so, to what extent and the reasons for the increase ; and

(c) whether this has resulted in general price rise especially with regard to consumer goods and if so, to what extent ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND
IN THE MINISTRY OF FOOD AND
CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI
RAO) : (a) and (b). The issue prices of all varieties of rice have been increased by Rs. 20/- per quintal with effect from 16.1.84, that of wheat by Rs. 1/- per quintal with effect from 15.4.83 and that of sugar by Rs. 25/- per quintal with effect from 1.2.84. Issue prices were increased to neutralise the

effect of increased support prices in the case of paddy and wheat and to offset the increased cost of production in the case of sugar.

(c) Issues of wheat, sugar and rice, are made through the public distribution system at highly subsidised rates. The present increase in their issue prices, is not likely to contribute to any overall increase in the market prices of consumer goods.

**Development of Industrial Estate
Violating NCR Plan**

449. SHRI MADHAVRAO SCINDIA :
Will the Minister of WORKS AND
HOUSING be pleased to state :

(a) whether a sub-group in his Ministry has in a paper pointed out that development of industrial estates like NOIDA and Kundli has been made in complete violation of the National Capital Region concept ;

(b) if so, the details of the points made out in the paper ; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :
(a) Yes.

(b) Neither NOIDA nor Kundli were envisaged for development in the Delhi Master Plan of 1962 and the NCR Plan approved in 1973 by the Advisory High Powered Board.

(c) The Government is making efforts to persuade the neighbouring States of U.P. and Haryana to limit NOIDA's population to 5 lakh by 2001 AD and discourage the development of Kundli beyond its present level respectively.

Ban on Export of Farm Produce

450. SHRI MADHAVRAO SCINDIA :
Will the Minister of AGRICULTURE be
pleased to state :

(a) whether National Agriculture